केंद्रीय कमेटी की विस्तारित बैठक

(7 से 10 अगस्त, विजयवाड़ा)

में स्वीकृत

राजनीतिक प्रस्ताव

राजनीतिक प्रस्ताव

अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति

1.1 19 वीं कांग्रेस के बाद गुजरे समय में विश्व पूंजीवादी व्यवस्था का ऐसा संकट देखने को मिला है, जो 1930 के दशक की महामंदी के बाद का उसका सबसे बड़ा संकट है। इस संकट ने, वित्तीय पूंजी से संचालित विश्वीकरण की अवहनीयता को रेखांकित किया है। अमरीका में राष्ट्रपति ओबामा के सत्ता में आने के साथ जो बदलाव हुआ उससे अमरीका की विश्व रणनीति में और अपना प्रभुत्व बनाए रखने की उसकी कोशिशों में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है। बहुध्रुवीयता की दिशा में रुझान ताकतवर हुआ है और क्षेत्रीय सहयोग का रुझान बढ़ा है, खासतौर पर लातीनी अमरीका में। विश्व आर्थिक संकट के असर से, नव-उदारवादी नीतियों के प्रतिरोध को और विकल्पों के उभरने की संभावनाओं को मजबूती मिली है।

विश्व आर्थिक संकट

1.2 जो संकट सामने आया सीधे-सीधे, नव-उदारवादी पूंजीवाद के तहत, वित्तीय पूंजी-संचालित वृद्धि का परिणाम है। 2009 में विश्व अर्थव्यवस्था में 1 फीसद से ज्यादा का संकुचन हुआ था। आर्थिक सहयोग व विकास संगठन (ओ ई सी डी) में शामिल विकसित पूंजीवादी देशों के सकल घरेलू उत्पाद में 3 फीसद से ज्यादा की गिरावट आयी थी। 2009 में विश्व व्यापार, इससे पिछले साल के मुकाबला 10 से ज्यादा घट गया था। यह समझ कर कि विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं (जी-7) अकेले इस संकट का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, जी-20 के माध्यम से विकासशील देशों को भी विश्व अर्थव्यवस्था को संकट से उबारने के प्रयासों में शामिल किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार, राजकोषीय उत्प्रेरण (सार्वजनिक खर्चे बढ़ाने तथा करों में कटौतियां करने) के जो कदम जी-20 की सरकारों ने अपनाये हैं वे ही मिलकर 2009 में 820 अरब डालर तक पहुंच गए थे यानी जी-20 देशों का कुल-मिलाकर जितना सकल घरेलू उत्पाद बनता था, उसके 2 फीसद के बराबर।

1.3 बढ़े हुए सार्वजनिक खर्चों तथा करों में कटौतियों के बावजूद, विश्व अर्थव्यवस्था में वृद्धि की बहाली सुस्त ही बनी रही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान पेश किया है कि 2010 में विश्व अर्थव्यवस्था करीब 3 फीसद की दर से वृद्धि करेगी। इसमें भी विकसित अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ 1.3 फीसद की दर से वृद्धि करेंगी और विश्व व्यापार में 2.5 फीसद की दर से वृद्धि होगी। इसके विपरीत चीन ने, अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को उत्प्रेरण देने के लिए खर्चोंके एक बहुत भारी कार्यक्रम के बाद, 2009 में 8.7 फीसद की वृद्धि दर दर्ज करायी है। इस गंभीर संकट का बोझ विकसित पूंजीवादी देशों में मजदूरों तथा गरीबों पर पड़ा है। ओ ई सी डी देशों में बेरोजगारी की औसत दर, 2008 के 6 फीसद के स्तर से बढ़कर, 2009 में करीब 9 फीसद पर पहुंच चुकी थी और 2010 के अप्रैल तक भी 8.7 फीसद के स्तर पर बनी हुई थी।

1.4 मौजूदा संकट नैगम दीवालों से भड़का है, जिन्हें विशालकाय बेल-आउट पैकेजों के जरिए संभाला जा रहा था। इसके बाद, संप्रभु (राष्ट्रों) के दीवालों का संकट उठ खड़ा हुआ है।

योरप में संकट

1.5 आर्थिक संकट का जोर फिलहाल अमरीका से हटकर, योरप की तरफ चला गया है। योरप के संकट का विस्फोट हुआ ग्रीस में, जिसकी अर्थव्यवस्था पर विश्व आर्थिक संकट के असर से भारी चोट आयी थी। जब वृद्धि दर बैठ गयी, सरकार के गिरते हुए राजस्व ने 2009 के आखिर तक आते-आते राजकोषीय घाटे व सार्वजनिक ऋण को अवहनीय स्तरों तक बढ़ा दिया। इससे, ऋण चुकाने में संप्रभु (ग्रीस राष्ट्र) के विफल हो जाने की संभावनाओं से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में दहशत फैल गयी। अब ग्रीस के अधिकारियों ने अपनी

ऋण संबंधी देनदारियां पूरी करने के लिए, 110 अरब यूरो (145 अरब डालर) की अंतर्राष्ट्रीय सहायता के बदले में 2010 के मई में योरपीय संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ, खर्चे कम करने के एक बहुत भारी कार्यक्रम को लागू करने के समझौते पर दस्तखत किए। कमखर्ची के इन जनविरोधी कदमों में सरकारी वेतनों में कटौतियों, मजदूरियों व पेंशनों पर जाम थोपने, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने आदि के जरिए सार्वजनिक खर्चों में भारी कटौतियां करने और इसके साथ ही राजकोषीय घाटा कम करने के लिए, अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी करने के कदम शामिल हैं।

1.6 योरप में संकट कोई ग्रीस तक ही सीमित नहीं है। पुर्तगाल, स्पेन, आइरलेंड तथा इटली आदि देशों को भी, जहां 2008 के बाद से राजकोषीय घाटे बढ़ोतरी पर रहे हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सार्वजनिक ऋण में तेजी से बढ़ोतरी हुई है, अपनी ही सरकारों द्वारा थोपे जा रही घाटों व सार्वजनिक ऋण में भारी कटौतियों की तगड़ी मार झेलनी पड़ रही है। इंग्लेंड (यू के) तथा जर्मनी ने भी, सरकारी खर्चों में तेजी से तथा भारी कटौतियों की घोषणा की है।

1.7 इन कमखर्ची के कदमों के खिलाफ समूचे योरप में और खासतौर पर ग्रीस, पुर्तगाल व फ्रांस में बड़ी-बड़ी विरोध कार्रवाइयां व हड़तालें हो रही हैं। ग्रीस में मजदूर वर्ग ने तथा अन्य तबकों ने एक के बाद एक आम हड़तालें व अन्य विरोध कार्रवाइयां आयोजित की हैं। इसके साथ ही साथ, इस संकट तथा बढ़ती हुई बेरोजगारी के चलते, योरप के विभिन्न देशों में धुर-दक्षिणपंथी तथा नस्लवादी ताकतों को बल मिल रहा है।

नव-उदारवादी पूंजीवाद के विरुद्ध संघर्ष

1.8 बहरहाल, साम्राज्यवादी देश, जिनकी पीठ पर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी का हाथ है, इसकी कोशिश कर रहे हैं कि विश्वीकरण में निहित आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखा जाए और जल्द से जल्द नव-उदारवादी नीतियों को ही आगे बढ़ाने के प्रयत्न जारी रखे जाएं। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी द्वारा भड़काए गए ऋण संकट तथा उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नव-उदारवादी सरकारों द्वारा थोपे जा रहे कमखर्ची के कदमों के खिलाफ योरप में जारी जनसंघर्ष, नव-उदारवाद के प्रतिरोध के द्योतक हैं। विश्व आर्थिक संकट ने साम्राज्यवादी वित्त से संचालित विश्वीकरण की प्रक्रिया की भंगुरता तथा अवहनीयता को उजागर कर दिया है। इसने नव-उदारवादी पूंजीवाद के विकल्पों के लिए संघर्ष का रास्ता खोला है।

ओबामा के राष्ट्रपतित्व में

1.9 2009 की जनवरी में राष्ट्रपति बराक ओबामा के नेतृत्व में अमरीका में नया प्रशासन आया था। उसके बाद से यह स्पष्ट हो गया है कि अमरीका की विश्व रणनीति में और उसके विदेश नीति संबंधी लक्ष्यों में कोई उल्लेखनीय बदलाव नहीं आया है। जो बदलाव हुए हैं, स्वर तथा शैली में ही हुए हैं। ओबामा ने राष्ट्रपति पद उस समय संभाला, जब वित्तीय संकट द्वारा अमरीका को जकड़ में लिया जा चुका था और जब बुश प्रशासन द्वारा सैन्य बल का आक्रामक उपयोग, इराक तथा अफगानिस्तान में अंधी गली में पहुंच चुका था। ओबामा प्रशासन ने बुश के दौर के इकतरफावाद से दूर हटने की कोशिश की है। इसके लिए उसने योरप के साथ संवाद पुल फिर से बनाने तथा अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का और अपनी राजनीतिक व कूटनीतिक रणनीति के लिए रूस व चीन का सहयोग हासिल करने के लिए, उनके साथ राब्ता कायम करने का प्रयास किया है। अमरीका, रूस के साथ अपने संबंधों को नये सिरे से चालू (रीसैट) करने की कोशिश कर रहा है।

1.10 बहरहाल, नया रुख अपनाने का पहले जो वादा किया गया था उसके विपरीत, ओबामा के प्रशासन के डेढ़ साल में अमरीका ने नाभिकीय मुद्दे पर ईरान को निशाना बनाए रखना जारी रखा है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा

परिषद से ईरान के खिलाफ पाबंदियों का चौथा चक्र मनवाने के लिए उसने पहल की है। इसके अगले कदम के तौर पर उसने ईरान के खिलाफ और उसके साथ व्यापार व वाणिज्य के रिश्ते रखने वालों के खिलाफ और कड़ी पाबंदियों का एलान किया है। यह इसके बावजूद किया गया है कि पहले खुद अमरीका तथा उसके सहयोगियों द्वारा सुझाए गए रास्ते पर ही, नाभिकीय ईधन की अदला-बदली के एक समझौते के लिए ब्राजील तथा तुर्की ने ईरान की रजामंदी हासिल कर ली थी।

1.11 फिलिस्तीन के प्रश्न के एक न्यायपूर्ण समाधान में मदद करने का वादा करने के बावजूद, ओबामा प्रशासन दक्षिणपंथी इस्राइली सरकार की विस्तारवादी नीति पर अंकुश लगाने में विफल रहा है। इस्राइली सरकार कब्जाए गए इलाकों में और यरूशलम में, नयी बस्तियां बसा रही है। गाज़ा बेड़े पर इस्राइली हमले के बाद भी उसे एक अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग का समर्थन करना मंजूर नहीं हुआ है। वह अब भी इस्राइली हठधर्मिता तथा हमलावर तेवरों का बचाव करना जारी रखे हुए है।

1.12 इराक में अमरीका एक ऐसा टिकाऊ निजाम खड़ा करने की जद्दोजेहद में लगा हुआ है, जिसको जनतांत्रिक मुखौटा पहनाया जा सके। चुनाव के बाद चार महीने गुजर चुके हैं लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किस तरह की सरकार बनेगी। इराक के तेल संसाधनों की लूट और उसे आर्थिक रूप से परनिर्भर बनाकर छोड़ा जाना, गौरतलब विशेषता है। ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण, दक्षिण एशिया व मध्य एशिया जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में वर्चस्व कायम करने की मुहिम के पीछे छुपा हुआ है।

1.13 ओबामा प्रशासन ने एलान किया था कि अफगानिस्तान और वहां युद्ध के समापन को अपनी प्राथमिकता बनाएगा। इसी को ध्यान में रखते हुए ओबामा ने वहां 30 हजार और अमरीकी सैनिक भेजे थे। अब वहां नाटो का समूचा बल 1,50,000 सैनिकों का है। अमरीका ने ''अफ-पाक'' नीति गढ़ी है जिसके तहत अलकायदा के खिलाफ संघर्ष में अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान, दोनों को जोड़कर युद्धस्थल की तरह देखा जा रहा है। युद्ध के नौ वर्ष बीत जाने के बाद भी, तालिबान के दबाए जाने के कोई आसार नहीं हैं। अमरीका को ऐसे राजनीतिक समझौते पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, जिसके तहत तालिबानी तत्वों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल किया जा सके। चूंकि बागी-विरोधी रणनीति और एक टिकाऊ अफगानी सरकार की स्थापना के रास्ते पर कोई प्रगति नहीं हो रही है, अमरीका तथा नाटो को आने वाले दिनों में सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा।

इस्राइली हमलावरपन

1.14 पश्चिम एशिया टकराव का एक प्रमुख स्थल बना हुआ है। इस्राइल ने गाज़ा पर नृशंस हमला किया और 2009 की जनवरी में उस पर कब्जा कर लिया। उसकी अंधाधुंध गोलाबारी तथा हवाई बमबारी में करीब 1400 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर असैनिक थे। वह गाज़ा की नाकेबंदी उठाने से इंकार कर रहा है और ईरान व लेबनान पर सैन्य हमलों की धमकियां दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में जलपोतों के गाज़ा बेड़े पर उसके नौ लोगों की हत्या कर देने की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भर्त्सना हुई है और मुस्लिम जगत के अपने इकलौते सहयोगी, तुर्की के साथ उसके रिश्ते टूट गए हैं।

लातीनी अमरीका

1.15 लातीनी अमरीका में कुछ देशों में वामपंथी ताकतों का आगे बढ़ना तथा अपनी हैसियत को मजबूत करना जारी है। वेनेजुएला ने अपने तेल क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण करने और अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करने के और कदम उठाए हैं। 2009 में तीन देशों में वामपंथ ने चुनाव जीते। बोलीविया में राष्ट्रपति चुनाव में इवो मोरालेस को दोबारा चुना गया। उरुग्वे में संसदीय व राष्ट्रपति चुनावों में वामपंथी गठबंधन ने जीत हासिल की। अल-सल्वाडोर में राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथ ने जीत हासिल की।

1.16 अमरीका, ऐसी ताकतों का रास्ता काटने की कोशिशों में लगा हुआ है, राष्ट्रीय संप्रभुता का इजहार कर रही हैं और नव-उदारवादी नीतियों के विकल्प के रास्ते पर चलने के लिए प्रयास कर रही हैं। अमरीका ने कोलंबिया में सात सैन्य अड्डे कायम करने के लिए, उसके साथ एक समझौते पर दस्तखत किए हैं। उसने तख्तापलट के बाद होंडूरास में स्थापित किए गए निजाम को परोक्ष समर्थन दिया है। लातीनी अमरीकी देशों की सर्वमान्य भावनाओं के खिलाफ अमरीका ने, क्यूबा की अपनी अवैध नाकेबंदी बनाए रखी है।

क्षेत्रीय सहयोग

1.17 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ''क्षेत्रीयता'' का रुझान ज्यादा खुलकर सामने आया है। लातीनी अमरीका में अल्बा, मर्कोसुर तथा रियो ग्रुप, सभी ने विभिन्न मंचों पर क्षेत्रीय सहयोग को आगे बढ़ाया है। अमरीका के जनगणों के लिए बोलीवारीय गठबंधन (एल्बा) में नौ देश शामिल हैं, जो आर्थिक व सामाजिक गतिविधियों में सहयोग कर रहे हैं। दस देशों के आसियान मंच ने आर्थिक व क्षेत्रीय सहयोग में काफी प्रगति की है। शांघाई सहयोग संगठन बराबर प्रगति करता रहा है। रूस में येकतेरिनबुर्ग में चार देशों (ब्राजील, रूस, भारत तथा चीन) के शासन-प्रमुखों की बैठक के बाद से, ब्रिक प्रक्रिया ने गति पकड़ी है। सार्क ही अपवाद है और दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय सहयोग पीछे बना रहा है। इस तरह के क्षेत्रीय मंचों का विकास, बहु-ध्रुवीयता को मजबूत करने की दिशा में जाने वाले रुझान का हिस्सा है।

पर्यावरण बिगड़ाव के खिलाफ संघर्ष

1.18 कोपेनहेगन में हुए पर्यावरण में बिगाड़ पर शिखर सम्मेलन किसी कानूनी तौर पर बाध्यकर समझौते तक पहुंचने में विफल रहा। इस निराशाजनक नतीजे के लिए मुख्य रूप से अमरीका व अन्य विकसित देशों का रुख तथा उनकी कार्यनीति ही जिम्मेदार है। अमरीका तथा उसके सहयोगियों की कोशिशों की दिशा यही थी कि क्योटो प्रोटोकॉल के सांचे तथा उसके सिद्धांतों के साथ ही छेड़-छाड़ की जाए। विकसित देशों के प्रतिरोध और ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत तथा चीन से गठित बेसिक ग्रुप के एकजुट रुख ने ही भविष्य की वार्ताओं को जिंदा बनाए रखने की गुंजाइश को बचाया। पर्यावरण बिगड़ाव के मुद्दे पर धनी औद्योगीकृत देशों और विकासशील देशों के बीच का अंतर्विरोध ही एक प्रमुख कारक बनकर सामने आया है। यह सुनिश्चित करने के लिए संघर्ष कि विकसित देश अपने उत्सर्जनों में गहरी कटौतियों के लिए राजी हों, औद्योगीकृत तथा विकासशील देशों के बीच विभेदीकरण के सिद्धांत को स्वीकार करें और मुख्य बोझ उठाएं, आने वाले दिनों की एक प्रमुख विशेषता होने जा रहा है।

दक्षिण एशिया

1.19 **पाकिस्तानः** पाकिस्तान को अतिवादी तथा तत्ववादी गुटों की बढ़ती हुई हिंसा झेलनी पड़ी है। इस तरह के हमले सीमावर्ती प्रांतों में और लाहौर व करांची जैसे शहरों में हो रहे हैं। पाकिस्तानी तालिबान के खिलाफ अमरीकी चालक रहित विमानों (ड्रोन) के हमलों ने जनमत को भड़काया है और आतंकवादियों के जवाबी हमलों की ओर भी ले गए हैं। पाकिस्तान की राष्ट्रीय संसद ने एक दूर तक जाने वाला संविधान संशोधन अपनाया है, जो संसदीय व्यवस्था पर राष्ट्रपति के अतिक्रमण को खत्म करता है और प्रांतों को महत्वपूर्ण शक्तियां देता है। यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे अगर अमल में लाया जाता है तो इस देश की व्यवस्था के जनतांत्रिक व संघीय आधार को इससे ताकत मिलेगी।

1.20 **बांग्लादेशः** 2009 में पूर्ण संसदीय जनतंत्र की बहाली एक उपलब्धि थी। अवामी लीग के नेतृत्ववाले गठबंधन की जीत तथा शेख हसीना सरकार का कायम होना और बांग्लादेश का धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया जाना, उन दक्षिणपंथी व तत्ववादी ताकतों के लिए एक धक्का था, जो अब भी खतरा बनी हुई हैं। आर्थिक

संकट की इस देश पर कड़ी मार पड़ी है। खाद्य सामग्री की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और मेहनतकश जनता के जीवन स्तर में गिरावट आयी है। भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग मजबूत हुआ है। बांग्लादेश की सरकार ने, अपनी सीमाओं के अंदर से काम करते रहे उल्फा जैसे उग्रवादी गुटों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ कदम उठाए हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार व परागमन की सुविधाओं का विस्तार हुआ है।

1.21 **नेपाल:** माओवादी नेता प्रचंड के इस्तीफा देने के बाद से, राजनीतिक हालात में एक गतिरोध बना हुआ है। एक साल गुजर जाने के बाद, इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश प्रधानमंत्री के पद से माधव कुमार नेपाल के इस्तीफे तक ले गयी है। नया संविधान सूत्रबद्ध करने की राजनीतिक प्रक्रिया को आगे ले जाने के लिए, प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के बीच एक आम राय का होना जरूरी है। शांति प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए ताकि नेपाल को एक गणतांत्रिक व जनतांत्रिक व्यवस्था मिल सके।

1.22 **श्रीलंका:** लिट्टे की शिकस्त तथा उसके सफाए से, ढ़ाई दशक लंबे गृहयुद्ध का अंत हो गया है। राजपक्षे सरकार ने विस्थापित तमिलों के लिए राहत व पुनर्वास के कदमों के साथ न्याय नहीं किया है। संसदीय चुनाव के बाद से सरकार ने, तमिल प्रश्न के समाधान के लिए अपनायी जाने वाली राजनीतिक प्रक्रिया को स्पष्ट नहीं किया है। एकीकृत श्रीलंका के दायरे में, तमिलभाषी इलाकों के लिए स्वायत्तता का प्रावधान किया जाना जरूरी है। यह एक ऐसा जरूरी कदम है जिससे तमिलों को उनके अधिकार मिलने का और लंबे समय से लटकी पड़ी तमिल समस्या के समाधान का भरोसा दिलाया जा सकेगा। तमिल जनगण का पूर्ण पुनर्वास और तमिल प्रश्न के राजनीतिक समाधान की दिशा में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार को अपने कूटनीतिक व राजनीतिक प्रभाव का उपयोग करना चाहिए।

1.23 जैसाकि 19 वीं कांग्रेस के राजनीतिक प्रस्ताव में रेखांकित किया गया था, दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहां साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढ़ा है। इस क्षेत्र के ज्यादातर देश आतंकवाद तथा हिंसा के शिकार हैं, जिनकी जड़ें धार्मिक संकीर्णतावाद तथा सांप्रदायिकता में हैं। दुनिया भर में सबसे ज्यादा ग्रामीण गरीब दक्षिण एशिया में ही हैं और इन सभी देशों पर जनगण की आजीविका व जीवन स्तर पर, आर्थिक संकट का असर पड़ा है। दक्षिण एशिया की जनतांत्रिक व प्रगतिशील ताकतों के साथ, जो साम्राज्यवादी प्रभाव, नव-उदारवादी नीतियों तथा तत्ववाद की शक्तियों के खिलाफ लड़ रही हैं, सी पी आइ (एम) अपनी एकजुटता व्यक्त करती है।

निष्कर्ष

1.24 विश्व आर्थिक संकट ने अमरीका की आर्थिक शक्ति की गिरावट को भी सामने ला दिया है। चीन की आर्थिक ताकत बढ़ी है और प्रमुख विकासशील देश आर्थिक संकट का कहीं बेहतर तरीके से सामना कर पाए हैं। इसने बहु-ध्रुवीयता की ओर जाने वाले रुझान को और उत्प्रेरित किया है। विश्व आर्थिक संकट ने, साम्राज्यवादी विश्वीकरण द्वारा पाली-पोसी गयीं नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को उभारकर सामने ला दिया है। इन नीतियों तथा अमरीका के वर्चस्ववादी प्रयासों का अलग-अलग हद तक और निरंतर प्रतिरोध किया जा रहा है।

1.25 दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अपने प्रभुत्व का विस्तार करने के अमरीकी साम्राज्यवाद के प्रयासों का, सी पी आइ (एम) दृढ़तापूर्वक विरोध करेगी। वह क्यूबा को, फिलिस्तीनियों को तथा ईराकी जनगण को और साम्राज्यवादी हमलों व नाकेबंदी के खिलाफ लड़ रहे देशों व दूसरी तमाम शक्तियों को, सक्रिय रूप से अपना समर्थन देगी तथा उनके साथ एकजुटता जताएगी। सी पी आइ (एम), अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ का विरोध करने के लिए, देश के अंदर तमाम साम्राज्यवादविरोधी ताकतों को गोलबंद करेगी।

राष्ट्रीय परिस्थिति

यूपीए सरकार की आर्थिक नीतियां

2.1 कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार के पहले एक साल ने इसकी पुष्टि कर दी है कि वह नव-उदारवादी नीतियों को और तेज करने जा रही है। खुदरा व्यापार, उच्च शिक्षा, बैंकिंग, बीमा तथा प्रतिरक्षा जैसे क्षेत्रों को प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों के लिए और ज्यादा खोला जा रहा है जोकि राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर रूप से नुकसानदेह साबित होगा। भारत-अमरीका सीईओ मंच ही, कांग्रेस के नेतृत्ववाली सरकार के लिए एजेंडा तय कर रहा है। सरकार ने विनिवेश की आक्रामक मुहिम भी छेड़ रखी है। 25,000 करोड़ रु0 से ज्यादा मूल्य की सार्वजनिक हिस्सा पूंजी पहले ही 2009-10 के दौरान बेची जा चुकी है और इस साल सेल, हिंदुस्तान कॉपर तथा कोल इंडिया के शेयरों की बिक्री के जरिए, 40,000 करोड़ रु0 जुटाए जाने की योजना है। योजना आयोग निजी-सार्वजनिक भागीदारी (पी पी पी) परियोजनाओं के लिए जोर लगा रहा है। रेल्वे तथा बुनियादी ढ़ांचे का थोक के हिसाब से निजीकरण किए जाने का रास्ता बनाया जा रहा है। खनन नीति के चलते खनिज संसाधनों की बड़े पैमाने पर लूट हो रही है और अवैध खनन हो रहा है।

2.2 फरवरी 2010 में पेश किए गए बजट में पैट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों में बढ़ोतरी के जरिए जनता पर 60,000 करोड़ रु0 का अतिरिक्त बोझ डाला गया था। दूसरी तरफ, नैगम कंपनियों को और संपन्न तबकों को प्रत्यक्ष करों में 26,000 करोड़ रु0 की अतिरिक्त रियायतें दी गयी थीं। इसके तीन महीने के अंदर-अंदर मिट्टी के तेल के समेत सभी पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में दोबारा भारी बढ़ोतरी कर दी गयी। सरकार जो प्रत्यक्ष कर संहिता 2011 से अपनाना चाहती है, उसमें उच्चतर आय श्रेणियों पर लगने वाले आय कर की दरों में भारी कमी करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा इसमें नैगम कर तथा संपत्ति कर की दरों में कटौतियां करने का प्रस्ताव है। आर्थिक नीतियां इस तरह गढ़ी गयी हैं जिससे आम जनता पर बोझ डालने की कीमत पर, बड़े कारोबार के मुनाफों को ऊंचे स्तर पर बनाए रखा जा सके। नव-उदारवादी नीतियों के आगे बढ़ाए जाने के जरिए, आर्थिक तानाशाही ज्यादा से ज्यादा अभिव्यक्त हो रही है।

2.3 कृषि के क्षेत्र में नीतियों का जोर, नैगम क्षेत्र की और ज्यादा घुसपैठ को बढ़ावा देने और किसानों को मिलने वाली राजकीय सहायता से हाथ खींचे जाने पर है। उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रण-मुक्त करने तथा उर्वरक सब्सीडियों में भारी कटौती करने की बदनीयती के साथ, यूरिया की कीमतें बढ़ा दी गयी हैं और अन्य उर्वरकों की कीमतों को विनियंत्रित कर दिया गया है। भारत-अमरीका कृषि ज्ञान पहल, एक ऐसा औजार है जिसके सहारे बहुराष्ट्रीय निगमों के हितों को आगे बढ़ाया जा रहा है। भारत में कृषि शोध को अमरीकी प्रौद्योगिकी व बड़ी पूंजी पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर बनाया जा रहा है। आसियान व योरपीय यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए, कृषि में व्यापार उदारीकरण को आगे बढ़ाया जा रहा है।

2.4 सरकार आम आदमी के लिए अपने वचनों से भी पीछे हट रही है। ग्रामीण विकास, नरेगा, स्वास्थ्य व शिक्षा की मदों में, कल्याणकारी खर्चों में बढ़ोतरी नहीं हुई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा उसका विस्तार करने और खाद्य सब्सीडी में बढ़ोतरी करने की जगह पर, सरकार द्वारा प्रस्तावित खाद्य अधिकार विधेयक, गरीबों के वर्तमान खाद्य अधिकार में ही कटौती करना चाहता है और लक्षित (टार्गेटेड) प्रणाली को बनाए रखना चाहता है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम अनाज से फटे पड़ रहे हैं और इस अनाज का काफी हिस्सा सड़ रहा है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा के तथा अन्य कल्याणकारी कदम, पूरी तरह से दिखावा साबित हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नव-उदारवादी हमला छेड़कर, सभी स्तरों पर शिक्षा का केंद्रीयकरण व व्यापारीकरण किया जा रहा है। विदेशी शिक्षा संस्थान विधेयक का एक ही नतीजा होगा कि

शिक्षा के क्षेत्र के विदेशी खिलाड़ी, यहां शिक्षा की अपनी दूकानें खोलेंगे, जिनमें अनाप-शनाप फीस बटोरी जाएगी और छात्रों को निचोड़ा जाएगा।

जनता पर प्रतिकूल प्रभाव

2.5 सरकार की सबसे बड़ी विफलता, मुद्रास्फीति पर और खाद्य व अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने में उसकी असमर्थता के रूप में सामने आयी है। सालाना मुद्रास्फीति की दर 2010 की मई में 10 फीसद से ऊपर निकल गयी और खाद्य मुद्रास्फीति की दर 2010 के जून में 16 फीसद से ऊपर बनी हुई थी। खाद्य मुद्रास्फीति की यह ऊंची दर तब चल रही है, जब भारत में पांच साल से कम आयु के 43 फीसद बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। अनाज, दालों, दूध तथा चीनी के दाम के अलावा गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों का भी ऊपर चढ़ना शुरू हो गया है। भारत की 13 फीसद से ऊपर की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति, जी-20 में शामिल सभी देशों में सबसे ज्यादा है। इसके बावजूद गेहूं, चने की दाल, आलू जैसी आवश्यक वस्तुओं के मामले में सट्टेबाजाराना वायदा कारोबार की इजाजत दी जा रही है और पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों को नियंत्रण मुक्त किया जा रहा है।

2.6 सरकार 2009-10 में हासिल हुई 7.4 फीसद की वृद्धि दर का ढोल पीटने में लगी हुई है। लेकिन, कुल वृद्धि दर का यह आंकड़ा विकास की इस प्रक्रिया की असंतुलित प्रकृति को छुपा लेता है। 2009-10 में खेती की वृद्धि दर सिर्फ 0.2 फीसद रही थी। इतनी कम वृद्धि दर, 2009-10 की 7.5 फीसद की वृद्धि दर के बाद रही थी। यह स्पष्ट है कि यूपीए सरकार के पिछले कार्यकाल में कृषि उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई थी, उसे बनाए नहीं रखा जा सका है। 2009-10 में खाद्यान्न उत्पादन में 7.5 फीसद की गिरावट हुई है। जो वृद्धि हो रही है, अपनी प्रकृति में रोजगारहीन वृद्धि है और मुख्यत: सेवाओं के क्षेत्र में ही केंद्रित है। संगठित क्षेत्र में लगी श्रम शक्ति का अनुपात बहुत ही थोड़ा बना हुआ है और इसमें से भी 40 से 50 फीसद तक हिस्सा कैजुअल या ठेका मजदूरों का है, जिन्हें कोई भी वैधानिक लाभ हासिल नहीं हैं। कुल श्रम शक्ति में से आधे से ज्यादा हिस्सा, खेती में ही काम कर रहा है। इस असंतुलित वृद्धि प्रक्रिया का नतीजा यह हुआ है कि संपदा का भारी केंद्रीयकरण हो रहा है और इसके साथ ही साथ आय की असमानताएं तेजी से बढ़ रही हैं।

2.7 किसानों की आत्महत्याओं का रुझान रुका नहीं है। 1999 से 2008 के बीच की अवधि में, देश भर में 2 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। किसानों की आत्महत्या की 60 फीसद घटनाएं पांच राज्यों में ही हुई हैं--महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। खुली तथा छुपी हुई बेरोजगारी के ऊंचे स्तर से कोई राहत नहीं मिली है। असंगठित क्षेत्र उद्योगों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एन सी ई यू एस) की रिपोर्ट के अनुसार, 2004-05 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कुल रोजगार 45 करोड़ 60 लाख था, जिसमें से अनौपचारिक क्षेत्र का हिस्सा 39 करोड़ 30 लाख था यानी 2004-05 में कुल श्रम शक्ति में असंगठित क्षेत्र का हिस्सा 86 फीसद था। असंगठित क्षेत्र में लगे 39 करोड़ 30 लाख मेहतनकशों में से, 25 करोड़ 10 लाख खेती में लगे हुए थे और शेष 14 करोड़ 20 लाख गैर-कृषि क्षेत्र (उद्योग व सेवाओं) में लगे हुए थे।

2.8 नव-उदारवादी निजाम के तहत आर्थिक वृद्धि की प्रक्रिया संगठित क्षेत्र में मुट्ठीभर लोगों के लिए ही बहुत ही सीमित संख्या में औपचारिक रोजगार के अवसर पैदा करने में समर्थ है जबकि अवाम को अनौपचारिक क्षेत्र की दलदल में धकेल दिया जाता है और स्वरोजगार का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर किया जाता है तथा उन्हें असुरक्षा व दरिद्रता का जीवन जीना पड़ता है। सरकार इसी तबके के बीच ''समावेशी विकास'' का नारा चलाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वह कल्याणकारी कार्यक्रमों के जरिए अतिरिक्त उत्पाद/ मुनाफों के एक छोटे से हिस्से का पुनर्वितरण कर रही है, जबकि नव-उदारवादी निजाम में कोई खलल नहीं पड़ रहा है।

आज इन्हीं तबकों को आर्थिक मंदी, रोजगार हानि, कृषि की बदहाली और खाने-पीने की चीजों की कीमतों में कमरतोड़ मुद्रास्फीति का सामना करना पड़ रहा है।

अलग-अलग वर्गों पर असर

2.9 आर्थिक उदारीकरण के दो दशकों का भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों पर अलग-अलग असर पड़ा है। उदारीकरण की प्रक्रिया का संचालक तथा सबसे बड़ा लाभान्वित, बड़ा पूंजीपति वर्ग रहा है, जिसकी परिसंपत्तियों तथा ताकत में भारी बढ़ोतरी हुई है। राजनीति तथा नीति निर्धारण पर इसका सीधे असर पड़ा है। ***फोर्ब्स*** पत्रिका के अनुसार भारत में डालर अरबपतियों (1 अरब डालर यानी करीब 4,600 करोड़ रु0 से ज्यादा की संपदा के स्वामियों) की संख्या, जो 2004 में 9 ही थी, 2010 तक बढ़कर 49 पर पहुंच चुकी थी। निजी क्षेत्र के दस सबसे बड़े नैगम घरानों की परिसंपत्तियां, 2003-04 के 3 लाख 54 हजार, करोड़ रु0 के स्तर से बढ़कर 2007-08 तक तीन गुनी हो गयी थीं तथा 10 लाख 34 हजार, करोड़ रु0 के स्तर पर पहुंच चुकी थीं।

2.10 भूस्वामियों तथा धनी किसानों के बीच से, गैर-कृषि पूंजी के साथ कहीं ज्यादा पूंजीवादी संबंध कायम हुए हैं तथा कड़ियां जुड़ी हैं। ग्रामीण संपन्नों के ये वर्ग भी उदारीकरण के पक्ष में हैं, जबकि कुछ मुद्दों पर ही उनके हित उदारीकरण से टकराते हैं।

2.11 उदारीकरण की प्रक्रिया द्वारा पोषित वृद्धि से मध्य वर्ग का एक हिस्सा लाभान्वित हुआ है। यह तबका, जिसका प्रभाव बढ़ गया है, आमतौर पर सत्ताधारी प्रतिष्ठान के पक्ष में है।

2.12 इन वर्गों के विपरीत ग्रामीण गरीब, जिनमें खेत मजदूर, गरीब किसान, दस्तकार तथा मध्यम किसानों के हिस्से आते हैं, बुरी तरह से कृषि संकट की मार झेल रहे हैं। नव-उदारवादी निजाम में यही तबके सबसे ज्यादा शोषित हैं। शहरी गरीब भी इसी श्रेणी में आते हैं, जिन्हें अनियमित रूप से थोड़ा-बहुत काम मिलता है। प्रवासी मजदूरों को अमानवीय कार्य-दशाओं का भी सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सेवाओं के क्षेत्र में स्वरोजगार में लगे लोगों का भी विशाल हिस्सा है, जो जैसे-तैसे गुजर करने लायक कमाई कर पाता है। इन शोषित श्रेणियों में बहुत बड़ा हिस्सा दलितों, आदिवासियों तथा अल्पसंख्यकों का है, जिन्हें सामाजिक उत्पीड़न भी झेलना पड़ता है।

2.13 पार्टी को इन तबकों के बीच काम करना होगा और जनसंगठनों के माध्यम से उन्हें संगठित करना होगा। अगर पार्टी के आधार का विस्तार करना है, तो हमें इन तबकों को उनके फौरी मुद्दों पर और मांगों पर संगठित करना होगा। जनता के विभिन्न तबकों पर पड़ रहे नव-उदारवादी निजाम के प्रभावों के खिलाफ और बड़े आंदोलन व संघर्ष छेड़ने के जरिए, ग्रामीण व शहरी इलाकों में मेहनतकश जनता के बीच एक ठोस आधार खड़ा करना होगा।

सांप्रदायिकता और आतंकवाद

2.14 लोकसभा चुनाव के बाद गुजरे अर्से में सांप्रदायिक संगठनों ने इसकी कोशिशें की हैं कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पैदा किया जाए और हिंसा भड़कायी जाए। पिछले एक साल के दौरान हैदराबाद, बरेली, अहमदाबाद तथा महाराष्ट्र में नांदेड़ में सांप्रदायिक हिंसा हुई है। उन राज्यों में जहां भाजपा का शासन है, अल्पसंख्यकों को--जिनमें मुसलमान तथा ईसाई दोनों शामिल हैं--निशाना बनाया जाना और उन पर हमले किया जाना जारी है। कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश में ऐसा नियमित रूप से हो रहा है। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव करने के लिए राज्य सरकारों की मशीनरी का भी उपयोग किया जाता रहा है। फर्जी मुठभेड़ में हत्याओं के सिलसिले में गुजरात के गृह राज्य मंत्री, अमित शाह की गिरफ्तारी, कानून व व्यवस्था की प्रणाली के साथ भीतरघात किए जाने को ही रेखांकित करती है।

2.15 भाजपा-आर एस एस जोड़ी सेतु समुद्रम नहर परियोजना और जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ मंदिर विवाद जैसे मुद्दों पर भावनाएं भड़काने की कोशिश करता रहा है। लेकिन उसे बड़े पैमाने पर जनता के बीच भावनाएं भड़काने में कामयाबी नहीं मिली है।

2.16 पिछले तीन वर्षों में एक नयी चीज उभरकर आयी है, हिंदुत्ववादी अतिवादी तत्वों का आतंकवादी हिंसा का सहारा लेना। 2007 के सितंबर में हुए मालेगांव विस्फोट की कड़ियां हिंदुत्ववादी अतिवादी ग्रुप से जुड़ी निकलीं। अब इन्हीं तत्वों के साथ अजमेर शरीफ विस्फोट तथा हैदराबाद के मक्का मस्जिद विस्फोट की कड़ियां भी जुड़ गयी हैं। गोवा में सनातन संस्था भी आतंकवादी हिंसा के लिए बमों का इस्तेमाल करती पायी गयी है। हिंदू आतंकी गुटों की मौजूदगी भाजपा-आर एस एस के उस पूर्वाग्रहग्रस्त प्रचार को बेनकाब कर देती है, जो आतंकवाद को मुस्लिम समुदाय के साथ ही जोड़कर पेश करता है।

2.17 हिंदू सांप्रदायिकता के आतंकवादी गतिविधियों तक ले जाने के खतरों से जनता को खबरदार किया जाना चाहिए। इसके साथ ही साथ ऐसे मुस्लिम अतिवादी गुट भी हैं, जो आतंकवादी तरीकों का सहारा लेना जारी रखे हुए हैं। पुणे का बम विस्फोट इसी की एक मिसाल है। पॉपूलर फ्रंट ऑफ इंडिया की गतिविधियां, इसी का एक और सबूत हैं। केरल में उनके कार्यकर्ताओं ने एक लैक्चरर का हाथ ही काट डाला और पुलिस ने उनके दफ्तरों में बम तथा हथियार जब्त किए हैं। मुस्लिम हों या हिंदू, अतिवादियों के आतंकवाद का मुकाबला करना होगा। सांप्रदायिकता तथा आतंकवाद के खिलाफ अभियान जनता के बीच ले जाया जाना चाहिए और दोनों के बीच के अंतर्संबंध को बेनकाब किया जाना चाहिए।

माओवादी हिंसा

2.18 पिछले दो वर्षों में माओवादी हिंसा तथा हमलों में बढ़ोतरी हुई है। माओवादी गतिविधियां छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र व पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, आदिवासी इलाकों में केंद्रित हैं। माओवादी सिर्फ पुलिस बलों को ही निशाना नहीं बना रहे हैं बल्कि वे अपने राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाकर अंधाधुंध हिंसा कर रहे हैं, रेल व सड़क संचार को बाधित कर रहे हैं और स्कूलों व पंचायत भवनों को नष्ट कर रहे हैं।

2.19 माओवादी हिंसा की अराजक तथा आतंकवादी प्रकृति का आंखें खोलने वाला प्रदर्शन तब हुआ जब दांतेवाड़ा में उन्होंने एक बस को विस्फोट से उड़ा दिया, जिसमें आम नागरिक यात्रा कर रहे थे और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रैस पर भयावह हमला किया, जिसमें ट्रेन पटरी से उतर गयी और 149 यात्री मारे गए।

2.20 पिछले संसदीय चुनाव के बाद से, पश्चिम बंगाल में पश्चिमी मेदिनीपुर, पुरुलिया तथा बांकुड़ा जिलों में, करीब 150 सी पी आइ (एम) सदस्यों तथा समर्थकों की नृशंस हत्याओं के लिए, माओवादी दस्ते ही जिम्मेदार हैं। ये हमले, सी पी आइ (एम) के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की हिंसा के साथ तालमेल बैठाकर किए जा रहे हैं। दूसरी जगहों पर भी माओवादी गुट चुनावों के दौरान, भाड़े के सैनिकों वाले उद्देश्यों से, विभिन्न पूंजीवादी पार्टियों के साथ सौदे करते बताए जाते हैं। ठेकेदारों, स्थानीय व्यापारियों तथा विभिन्न अधिकारियों से जबरन चौथ तथा धन वसूली के जरिए, वे बड़े पैमाने पर धन बटोर रहे हैं, जिससे वे अपनी सशस्त्र हरकतों का खर्चा उठाते हैं।

2.21 माओवादी अतिवामपंथी दुस्साहसवाद के पतित रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे सी पी आइ (एम) को निशाना बनाने के जरिए, शासक वर्ग के ही हित साध रहे हैं। अन्य अतिवादी तथा अलगाववादी ताकतों के साथ भी उनकी कड़ियां जुड़ी हुई हैं। राज्य को पलटने के लिए सशस्त्र संघर्ष की माओवादी कार्यनीति के नतीजे, निर्दोष आदिवासियों के भीषण दमन और जनतांत्रिक आंदोलन व राजनीतिक गोलबंदी में विघ्न डाले जाने के रूप में सामने आते हैं।

2.22 माओवादी तमाम विकास गतिविधियां बंद कर देते हैं और इस तरह आदिवासी जन की वंचितता को बढ़ाते हैं। माओवादी खतरे से निपटने के लिए, संबंधित इलाकों में नागरिक प्रशासन बहाल किया जाना चाहिए ताकि राजनीतिक व विकास के काम हो सकें।

0 माओवादियों की विघटनकारी राजनीति तथा दीवालिया विचारधारात्मक स्थापनाओं को बेनकाब करने के जरिए, पार्टी को माओवादियों का मुकाबला करना होगा। उनकी क्रांतिकारी लफ्फाजी की असलियत सामने लायी जानी चाहिए क्योंकि पैटी-बुर्जुआ बुद्धिजीवी तबके के एक हिस्से के बीच उन्हें लेकर विभ्रम हैं।

0 उनकी निरर्थक हिंसा के खिलाफ, राजनीतिक विरोधियों के प्रति उनकी असहिष्णुता के खिलाफ और पश्चिम बंगाल में सी पी आइ (एम) कार्यकर्ताओं व समर्थकों की हत्याओं के खिलाफ, जनतांत्रिक जनमत को गोलबंद करना होगा।

0 आदिवासी आबादी वाले प्रमुख राज्यों में आदिवासी इलाकों में काम पर और जनसंगठनों को तथा पार्टी के प्रभाव को बढ़ाने पर, पार्टी को फौरन ध्यान देना चाहिए।

उत्तर-पूर्व

2.23 उत्तर-पूर्व के हालात की पहचान अब भी उन्हीं दुहरे लक्षणों से होती है: केंद्र सरकार का भेदभाव तथा उसके द्वारा उपेक्षा और अपवादस्वरूप त्रिपुरा को छोड़कर पूंजीवादी राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों तथा ठेकेदारों के भ्रष्ट गठजोड़ द्वारा केंद्रीय फंडों की चोरी। इसके चलते विभिन्न राज्यों में जनता का जो अलगाव हो रहा है, उसका इस्तेमाल करने की कोशिश फूटपरस्त व अलगाववादी ताकतों द्वारा की जाती है। असम में, उल्फा समेत सभी अतिवादी संगठन उल्लेखनीय हद तक कमजोर हुए हैं। ऐसी अतिवादी ताकतों के खिलाफ बांग्लादेश की सरकार के दृढ़ रुख अपनाने के चलते, उल्फा के शीर्ष नेताओं में से अनेक को भारत के हवाले किया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। यही इसके लिए उपयुक्त समय है कि केंद्र सरकार उल्फा तथा उत्तर-पूर्व में सक्रिय अन्य अतिवादी संगठनों के साथ बातचीत शुरू करे, ताकि कोई राजनीतिक समाधान निकाला जा सके। केंद्र सरकार को इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विकास करने के लिए और शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए, एक चौतरफा योजना तैयार करनी चाहिए।

2.24 यह क्षेत्र इथनिक विभाजनों तथा टकरावों से ग्रसित है। उत्तरी कछार हिल्स में तथा कार्बी आंग्लोंग हिल्स में, अतिवादी तत्वों ने हिंसक इथनिक टकराव भड़काए हैं। मणिपुर के राजमार्ग को आल नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन-मणिपुर और यूनाइटेड नगा काउंसिल द्वारा लंबे अर्से तक बंद कर के रखे जाने से, नगालिम यानी वृहत्तर नगालेंड की एन एस सी एन (आइ एम) की मांग से निकलने वाले खतरे रेखांकित हो गए हैं। पहचान की राजनीति का प्रसार, इथनिक आधार पर जनता की एकता को विभाजित कर रहा है तथा तोड़ रहा है और जनतांत्रिक आंदोलन के लिए एक बड़ी समस्या पेश कर रहा है। त्रिपुरा ही इसका अपवाद है जहां अनवरत राजनीतिक काम, विकास गतिविधियों और वाम मोर्चा सरकार की दृढ़ कार्रवाई के चलते, अतिवादी गतिविधियों पर अंकुश लगा है और आदिवासी-गैरआदिवासी एकता को बनाए रखा गया है।

जम्मू-कश्मीर

2.25 यहां आतंकवादी हिंसा तथा हमलों में उल्लेखनीय कमी हुई है। लेकिन, घाटी में जनता का अलगाव अब भी गहराई तक समाया हुआ है। शासन द्वारा दमन तथा मानवाधिकारों के हनन के मुद्दे पर समय-समय पर लोगों के गुस्से के विस्फोटों तथा जनविरोध कार्रवाइयों के जरिए इसी की अभिव्यक्ति होती है। नियंत्रण रेखा को पार कर रहे आतंकवादी करार देकर, तीन निर्दोष गांववालों को गोलियों से भून दिए जाने की वारदात, यह बताती है कि किस तरह जनता के भरोसे को और कमजोर किया जा रहा है। पथराव करने वाले युवाओं और

पुलिस व सी आर पी एफ के बीच जून से शुरू हुए टकराव में, करीब 50 युवाओं की जानें जा चुकी हैं। इसने हालात को और बिगाड़ा है।

2.26 अत्याचारों को और जनता के बुनियादी जनतांत्रिक अधिकारों के उल्लंघनों को फौरन रोका जाना चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। केंद्र सरकार को, तीव्र गति से विकास के लिए और युवाओं के लिए रोजगार पैदा करने के लिए, एक पैकेज तैयार करना चाहिए। यूपीए सरकार, संवाद व समाधान की प्रक्रिया को किसी सार्थक स्तर पर आगे बढ़ाने में विफल रही है। सरकार को अविलंब सभी तबकों के साथ संवाद की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। भारत-पाकिस्तान संवाद के फिर से चालू होने से, राजनीतिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वातावरण बनाने में मदद मिलेगी। राज्य के लिए अधिकतम स्वायत्तता और राज्य के अंदर तीनों क्षेत्रों के लिए क्षेत्रीय स्वायत्तता के प्रावधान के बिना, राजनीतिक समाधान की दिशा में कोई प्रगति नहीं हो सकती है।

केंद्र-राज्य संबंध

2.27 केंद्र सरकार, राज्यों की मौजूदा शक्तियों पर लगातार अतिक्रमण कर रही है। नव-उदारवादी कदमों तथा निजीकरण के जरिए केंद्र सरकार, विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की भूमिका को धकिया कर बाहर कर रही है और उन्हें केंद्र पर कहीं ज्यादा निर्भर बना रही है। नव-उदारवादी सुधारों के पालन को संसाधनों व अनुदानों के हस्तांतरण के लिए एक शर्त बनाया जा रहा है। केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं का भी इस उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। 13 वें वित्त आयोग ने अपने से पहले के दो आयोगों के रुझान को ही जारी रखा है और कहीं ज्यादा कड़ी शर्तें लगायी हैं। उसने संसाधनों के हस्तांतरण की एक शर्त के रूप में राज्यों को यह निर्देश दिया है कि कानून बनाकर, अपने राजकोषीय घाटे को सीमित करें। यह सरासर असंवैधानिक है। केंद्र सरकार, करों का 50 फीसद हिस्सा राज्यों के साथ बांटने से इंकार कर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र सरकार एक के बाद एक ऐसे विधेयक लाद रही है, जो शिक्षा में राज्यों की भूमिका को कमजोर करते हैं। राज्यपालों का उपयोग अक्सर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के हितों की सेवा के लिए किया जाता है या राज्यों की शक्तियों पर अतिक्रमण करने के लिए।

2.28 केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन के लिए सी पी आइ (एम) ने एक सर्वसमावेशी दस्तावेज तैयार किया है। केंद्र-राज्य संबंधों के पुनर्गठन के लिए और राज्यों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, समर्थन जुटाने का काम पार्टी को हाथ में लेना चाहिए।

तेलंगाना और पृथक राज्य

2.29 दिसंबर 2009 में टी आर एस अध्यक्ष की भूख हड़ताल के प्रत्युत्तर में केंद्र सरकार द्वारा पृथक तेलंगाना राज्य की मांग स्वीकार करने की घोषणा किए जाने के बाद, इस मांग को बल मिला। एकजुट आंध्र के पक्ष में जवाबी आंदोलन के सामने, केंद्र ने पांव पीछे खींच लिए और इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक आयोग का गठन कर दिया। केंद्र के जल्दबाज रुख के चलते, देश के विभिन्न हिस्सों में पृथक राज्य की मांगों को नया जीवन मिल गया। दार्जिलिंग में, गोरखालैंड के लिए विभाजनकारी आंदोलन जारी है।

2.30 इस मुद्दे पर सी पी आइ (एम) ने हमेशा एक अविचल रुख अपनाया है। वह भाषायी आधार पुनर्गठित हुए राज्यों के विभाजन के खिलाफ है। ये राज्य जनता के जनवादी आंदोलन के नतीजे में गठित हुए थे। अपेक्षाकृत बड़े राज्यों को तोड़कर छोटे-छोटे राज्य बनाना, संघीय ढांचे के लिए नुकसानदेह होगा। ये राज्य केंद्र पर कहीं ज्यादा निर्भर होंगे। पुन:, अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में से अनेक आसानी से बड़े व्यापारिक घरानों तथा बहुराष्ट्रीय निगमों के शिकार बन जाएंगे। जहां भी किसी राज्य के दायरे में कोई पिछड़े क्षेत्र हों, उन क्षेत्रों में

सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए। जहां आवश्यकता हो, क्षेत्रीय स्वायत्तता का प्रावधान किया जा सकता है।

अंध-क्षेत्रवादी तथा विभाजनकारी नारे

2.31 पृथक राज्य की मांगों के अलावा अंध-क्षेत्रवाद की ताकतें ''भूमि पुत्र'' के नारे लगा रही हैं और बहिरागतों को निशाना बना रही हैं। महाराष्ट्र में, ''महाराष्ट्र, महाराष्ट्रियों के लिए'' की मांग को लेकर, मनसे और शिव सेना में होड़ लगी हुई है। उन्होंने, मुंबई तथा अन्य शहरों में रह रहे उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया है। असम, मणिपुर तथा उत्तर-पूर्व में दूसरी जगहों पर भी कुछ अतिवादी गुटों ने, हिंदीभाषी प्रवासी मजदूरों और बहिरागतों पर हमले किए हैं। इस तरह के अंध-क्षेत्रवाद का मुकाबला करना होगा। वामपंथी व जनतांत्रिक शक्तियों को, ऐसी विभाजनकारी कट्टरता के खिलाफ मेहतनकश जनता के सभी तबकों की एकता का झंडाबरदार बनना चाहिए।

बड़ी पूंजी और राजनीति की मिलीभगत

2.32 यूपीए-द्वितीय की सरकार के कार्यकाल में बड़ी पूंजी और राजनीति की मिलीभगत उभरकर सामने आयी है। आइ पी एल प्रकरण, सरकार के पिछले कार्यकाल में हुआ दूरसंचार घोटाला और कर्नाटक के बेल्लारी बंधुओं जैसे खनन कारोबार-राजनीतिक माफिया का प्रभाव, ये सब राजनीतिक पर बड़ी तिजोरियों के बढ़ते असर को और उच्च स्तर के भ्रष्टाचार को दिखाते हैं, जो अब सरकार तथा शासक वर्गीय पार्टियों में उच्चतर हलकों तक पहुंच गया है। सार्वजनिक धन की इस लूट ने कॉमन वैल्थ खेलों को भी नहीं बख्शा है। पार्टी, भ्रष्टाचार तथा हरेक स्तर पर सार्वजनिक धन की लूट के खिलाफ संघर्ष छेड़ेगी।

2.33 भोपाल गैस कांड से जिस तरह निपटा गया है उसने और पिछले ही दिनों आए अदालत के फैसले ने यह उजागर कर दिया है कि किस तरह यूनियन कार्बाइड को किसी आपराधिक जवाबदेही के बिना और मामूली सी मुआवजा राशि में ही छोड़ दिया गया। एक के बाद एक आयी सरकारों ने, भोपाल कारखाना स्थल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए डॉव कैमीकल को जवाबदेह बनाने से भी इंकार किया है। यह एक बार फिर यही रेखांकित करता है कि किस तरह पूंजीवादी सरकारें, जनता के महत्वपूर्ण हितों की कीमत पर, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा बड़ी पूंजी के हितों की सेवा करती हैं। भोपाल गैस मामले में उन्होंने अवाम की जिंदगियों, सुरक्षा, स्वास्थ्य और न्याय व मुआवजे के उनके दावों की कीमत पर, इन हितों की सेवा की है।

2.34 नव-उदारवादी रुख का राजनीति पर भी सीधे असर पड़ रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में धन-बल का अभूतपूर्व इस्तेमाल, सीधे-सीधे नव-उदारवादी दृष्टिकोण का ही नतीजा है। यह समूची व्यवस्था को ही भ्रष्ट कर रहा है और ऐसी पार्टियों का काम करना मुश्किल बना रहा है जो बड़े पूंजीपति वर्ग तथा संपन्न वर्गों से नहीं जुड़ी हैं। पूंजीवादी पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों का चुनाव कर रही हैं, जो धनी व्यापारी हैं। चुनावों में धन-बल के इस्तेमाल को एक गंभीर मुद्दे के तौर पर उठाया जाना चाहिए। यह समूची राजनीतिक व्यवस्था को ही दूषित कर रहा है। ''पेड न्यूज'' या पैसे के बदले में खबर की परिघटना इसी गठजोड़ का नतीजा है। चुनावों में राजनीति में धन-बल की बाढ़ के खिलाफ तथा सार्वजनिक नीति निर्धारण के बढ़ते पैमाने पर बड़ी कारोबारी धन-शक्ति के पक्ष में मोड़े जाने के खिलाफ पार्टी को व्यापक स्तर पर अभियान चलाना होगा और उन पूंजीवादी पार्टियों को बेनकाब करना होगा जो ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करती हैं।

2.35 नव-उदारवाद और विश्व वित्तीय पूंजी का प्रभाव संसदीय जनतंत्र को ही खोखला कर रहा है। राजनीति में धन-बल तथा अपराधी-बल के जरिए जनतंत्र के साथ भीतरघात के साथ ही साथ, जनतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ती हुई पाबंदियां लगायी जा रही हैं। प्रदर्शन करने, जनसभाएं करने तथा आम हड़ताल करने के अधिकारों के साथ प्रशासनिक कदमों और न्यायिक हस्तक्षेपों के जरिए काट-छांट की जा रही है। जनता के

अधिकारों पर इस तरह की पाबंदियों का प्रचार करने तथा उन्हें उचित ठहराने के लिए, नैगम मीडिया का उपयोग किया जाता है।

चुनाव सुधार

2.36 इस संदर्भ में चुनाव सुधारों का मुद्दा महत्वपूर्ण हो जाता है। चुनाव कानूनों में संशोधन करने होंगे ताकि चुनाव में धन-शक्ति तथा अवैध कमाई के इस्तेमाल के खिलाफ कड़े प्रावधान किए जा सकें। सामान के रूप में और चुनाव सामग्री की आपूर्ति के रूप में, चुनाव के लिए शासन द्वारा सहायता की व्यवस्था शुरू की जानी चाहिए। मीडिया में चुनाव प्रचार के लिए समतापूर्ण पहुंच हासिल होना जरूरी है। कानून में संशोधन कर ''पेड न्यूज'' पर रोक लगायी जानी चाहिए और इसे एक चुनाव अपराध बनाया जाना चाहिए। चुनाव व्यवस्था में बुनियादी सुधार यह होना चाहिए कि आंशिक सूची व्यवस्था के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शुरू की जाए। इससे धन-बल तथा बाहु-बल का उपयोग एक हद तक दूर होगा।

विदेश नीति और रणनीतिक रिश्ते

2.37 यूपीए-द्वितीय की सरकार अमरीका के साथ रणनीतिक रिश्ते मजबूत करने की लाइन पर चल रही है। अमरीकी विदेश सचिव, हिलेरी क्लिंटन की भारत यात्रा के फलस्वरूप अंतिम उपयोग निगरानी समझौते पर दस्तखत किए गए हैं, जो भारत द्वारा खरीदे गए हथियारों की अमरीकी दलों द्वारा नियमित रूप से जांच किए जाने का रास्ता बनाता है। इससे अमरीका के लिए भारत को बड़े पैमाने पर हथियार बेचना संभव होगा। अमरीका से अरबों डालर के रक्षा उपकरण खरीदे जा रहे हैं।

2.38 भारत-अमरीका नाभिकीय सौदे के पालन के क्रम में भारत सरकार ने अमरीका को 10,000 मेगावाट के नाभिकीय विद्युत रिएक्टर खरीदने का वचन दिया है। भारत ने यह वचन भी दिया है कि एक कानून बनाया जाएगा जो, नाभिकीय दुर्घटना होने की सूरत में नाभिकीय रिएक्टरों के अमरीकी आपूर्तिकर्ताओं को जवाबदारी से बरी कर देगा। संसद में जो असैन्य नाभिकीय जवाबदारी विधेयक पेश किया गया है, भारतीय जनता की सुरक्षा, जिंदगियों तथा हितों की सरासर अनदेखी करते हुए, अमरीकी कंपनियों के हित साध रहा होगा। यह विधेयक विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को करीब-करीब पूरी तरह से जवाबदेही से बरी करता है।

2.39 आर्थिक सहयोग व कृषि शोध के क्षेत्रों में रणनीतिक गठजोड़ का पालन तेजी से आगे बढ़ रहा है। वित्तीय क्षेत्र में, खुदरा व्यापार में तथा उच्च शिक्षा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाने के सरकार के प्रस्ताव, इसी का परिणाम हैं। 2009 के नवंबर में प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान अमरीकी पूंजी के और ज्यादा निवेश का आश्वासन दिया गया था।

2.40 नवंबर 2009 में भारत ने तीसरी बार अंतर्राष्ट्रीय एटमी ऊर्जा एजेंसी (आइ ए ई ए) में ईरान के खिलाफ मतदान किया। यह मतदान ईरान की निंदा के एक ऐसे प्रस्ताव के पक्ष में किया गया है, जिसने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा उसके खिलाफ पाबंदियों का चौथा चक्र थोपे जाने का रास्ता बनाया था।

2.41 इस्त्राइल के साथ भारत के रणनीतिक रिश्तों को गहरा किया गया है। भारत अब इस्त्राइली हथियारों का सबसे बड़ा ग्राहक ही नहीं है बल्कि इस्त्राइल के साथ खुफिया व्यवस्था तथा सुरक्षा संबंधी गठजोड़ भी बढ़ाया गया है।

2.42 हालांकि भारत ब्रिक का सदस्य है और भारत, चीन व रूस के विदेश मंत्रियों के त्रिपक्षीय परामर्शों में हिस्सेदार रहा है, अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ उसे, एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चलकर, बहु-ध्रुवीयता को आगे बढ़ाने में एक प्रमुख तथा कारगर भूमिका अदा करने से रोकता है।

राजनीतिक परिस्थिति

कांग्रेस की स्थिति

2.43 पार्टी की 19 वीं कांग्रेस के बाद से कांग्रेस का आधार बढ़ा है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व में यूपीए गठजोड़ ने चुनाव में जीत तो हासिल की, पर उसे बहुमत नहीं मिल पाया। बहरहाल वह अपनी सरकार के लिए अनेक पार्टियों का समर्थन हासिल करने में कामयाब रहा। उसे शासक वर्ग के सबसे शक्तिशाली संस्तर, बड़े पूंजीपति वर्ग से भारी समर्थन मिला। कांग्रेस को इसलिए भी फायदा मिला कि उल्लेखनीय रूप से बड़ी संख्या में लोग नहीं चाहते थे कि एक सांप्रदायिक पार्टी--भाजपा--फिर से सरकार में आए। कांग्रेस पार्टी को मध्य वर्ग, अल्पसंख्यकों तथा युवाओं का कहीं ज्यादा समर्थन हासिल हुआ है।

2.44 कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश तथा बिहार जैसे राज्यों में, जहां पिछले दो दशकों के दौरान वह बहुत कमजोर हो गयी थी, अपने स्वतंत्र आधार को फैलाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल, यह आसानी से होने वाला काम नहीं है।

2.45 एक साल सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस पार्टी को इसका एहसास हुआ है कि उसे संसद में अपना काम-काज चलाने के लिए, विभिन्न पार्टियों के समर्थन की जरूरत है। कांग्रेस को अलग-अलग मुद्दों के हिसाब से उनका समर्थन हासिल करने के लिए सपा, राजद, बसपा तथा जनता दल (सैकुलर) जैसी पार्टियों के साथ हिसाब बैठाना पड़ता है। महंगाई से निपटने में अपनी विफलता और अमरीका व विदेशी पूंजी के पक्ष में जाने वाले विधेयकों को आगे बढ़ाने की अपनी कोशिशों की पृष्ठभूमि में, कांग्रेस यह देख रही है कि लोकसभा में उसके पास एक बहुत ही कमजोर सा बहुमत है और वह भी तिकड़मों के जरिए तथा सौदे पटाने के जरिए, कुछ धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों को अपने पक्ष में कर के जुटाना पड़ रहा है।

2.46 यूपीए गठबंधन के दायरे में कांग्रेस को, द्रमुक तथा तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के सामने, इन पार्टियों से संबंधित मामलों में झुकना पड़ता है। मिसाल के तौर पर दूरसंचार घोटाले के मामले में प्रधानमंत्री, द्रमुक के विरोध करने के चलते कार्रवाई नहीं कर पाए। कांग्रेस का नेतृत्व माओवादियों के साथ तृणमूल कांग्रेस के गठजोड़ को अनदेखा करता है।

भाजपा और उसके सहयोगी

2.47 लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा के नेतृत्व में जो अस्त-व्यस्तता आयी थी, उसे आर एस एस के हस्तक्षेप ने दूर किया और एक नया नेतृत्व बैठा दिया गया। बहरहाल, भाजपा अब भी अपना खोया आधार दोबारा हासिल नहीं कर पायी है और खुद को एक सुसंबद्ध विकल्प के रूप में पेश नहीं कर पा रही है। हालांकि, कुल मिलाकर भाजपा को धक्का लगा है, फिर भी गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में उसका आधार कमोबेश सुरक्षित बना रहा है। भाजपा, इन राज्यों में अपने परंपरागत आधार का सहारा लेकर पुनर्संगठित होने की कोशिश करेगी। वह ऐसे मुद्दों को उछालने की कोशिश करेगी, जिनके जरिए अपने सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ा सके।

2.48 अपनी अस्त-व्यस्तता के चलते भाजपा, अपने गठजोड़ को सुरक्षित नहीं रख पायी है। उसकी सहयोगी पार्टियों में से एक, असम की असम गण परिषद, उससे दूरी बनाने की कोशिश कर रही है। एक और सहयोगी, जनता दल (एकीकृत) के साथ, उसके रिश्तों में खिंचाव आया है।

क्षेत्रीय पार्टियों का रुख

2.49 क्षेत्रीय पार्टियां मोटे तौर पर क्षेत्रीय पूंजीपति वर्ग और ग्रामीण संपन्नों का प्रतिनिधित्व करती हैं। केंद्र के स्तर पर गठबंधन की राजनीति के आने के बाद से ये पार्टियां सिर्फ राज्य के स्तर पर सरकार बनाने का ही लक्ष्य

लेकर नहीं चलती हैं बल्कि केंद्र सरकार में हिस्सा पाने के लिए भी प्रयत्न करती हैं। इनमें से अनेक पार्टियों की राजनीति पर, भाजपा के प्रति उनके रुख के मामले में, अवसरवाद की छाप रहती है। अपने धर्मनिरपेक्ष चरित्र के बावजूद ये पार्टियां, अगर उनके हितों के माफिक पड़ता है तो, भाजपा से हाथ मिला लेती हैं। ऐसी क्षेत्रीय पार्टियां, जिन्हें राज्य के स्तर पर मुख्य विपक्ष के रूप में कांग्रेस का सामना करना पड़ता है, कांग्रेस से तो हाथ नहीं मिलाती हैं लेकिन उन्होंने यह साबित किया है कि अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए वे भाजपा के साथ हाथ मिला सकती हैं।

2.50 जैसाकि पार्टी की 16 वीं कांग्रेस ने दर्ज किया था, उदारीकरण तथा पूंजीवाद के फैलाव की प्रक्रिया के साथ, क्षेत्रीय पार्टियों ने भी उदारीकरण तथा निजीकरण की नीतियों को अपनाया है। लेकिन, विपक्ष में रहते हुए ये पार्टियां इन्हीं नीतियों का विरोध कर सकती हैं।

2.51 जैसाकि पार्टी की 18 वीं कांग्रेस ने कहा था, कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने नेतृत्ववाले गठबंधनों--यूपीए तथा एनडीए--के पीछे इस तरह की पार्टियों को गोलबंद करने की कोशिश कर रही हैं। यह जनता और वामपंथी तथा जनतांत्रिक शक्तियों के हित में नहीं है कि दो बड़ी पूंजीवादी पार्टियों के नेतृत्व में, द्विदलीय व्यवस्था कायम हो जाए। हमें ऐसी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ सहयोग करने तथा रिश्ते विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए, जो कांग्रेस या भाजपा में से किसी के साथ नहीं हैं। जनता के मुद्दों पर संयुक्त कार्रवाइयों, केंद्र-राज्य संबंधों आदि के लिए ऐसा सहयोग संभव है।

2.52 हाल के अनुभव ने दिखाया है कि इनमें से कुछ पार्टियां ढुलमुलपन दिखाती हैं और अपने रुख से बदलती रहती हैं। इनमें से कुछ पार्टियां अपने फौरी हित पूरे करने के लिए, कांग्रेस के साथ सौदेबाजी करती हैं। इसके बावजूद, हमारा रुख यही होना चाहिए कि गैर-कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों के साथ संसद में, मुद्दों के आधार पर सहयोग किया जाए। संसद के बाहर, जनता के मुद्दों पर हम उनके साथ संयुक्त कार्रवाइयां कर सकते हैं, ताकि आंदोलन को व्यापक बनाया जा सके।

2.53 महंगाई के खिलाफ 27 अप्रैल 2010 को अखिल भारतीय हड़ताल के लिए 13 गैर-कांग्रेसी, गैर-भाजपा पार्टियों के सफल आह्वान ने और 12 पार्टियों द्वारा 5 जुलाई की हड़ताल के दूसरे आह्वान ने, इस तरह की संयुक्त कार्रवाइयों की संभावनाओं को उजागर किया है। दूसरी ओर, लोकसभा में समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल के कटौती प्रस्तावों से पीछे हटने ने, उनकी ढुलमुल प्रकृति को ही दिखाया।

2.54 आज की परिस्थिति में, जब सी पी आइ (एम) पर हमला हो रहा है और वामपंथ को अलग-थलग करने की कोशिशें की जा रही हैं, यह जरूरी हो जाता है कि संसद में और संसद के बाहर भी, मुद्दों पर संयुक्त रुख अपनाने के लिए इन पार्टियों को खींचा जाए। नीतियों पर एक संयुक्त मंच या कार्यक्रम के उभरने के अर्थ में एक तीसरे विकल्प के उदय में वक्त लगेगा। तब तक राज्यों के स्तर पर, इनमें से कुछ पार्टियों के साथ चुनावी समझदारी कायम करना, संभव भी हो सकता है और जरूरी भी।

सी पी आइ (एम): प्रतिकूल हालात पर काबू पाएं

2.55 लोकसभा के चुनाव में पार्टी को धक्का लगने के बाद से, हमें प्रतिकूल हालात का सामना करना पड़ रहा है। पश्चिम बंगाल में, जहां पार्टी को चुनावी धक्के लगे हैं, पार्टी हमले झेल रही है। केरल में, लोकसभा चुनाव में हमें चुनावी नुकसान होने के बाद से, कांग्रेस के नेतृत्ववाला यूडीएफ सांप्रदायिक तथा प्रतिक्रियावादी ताकतों को अपने पीछे एकजुट करने में जुटा हुआ है। एक त्रिपुरा ही अपवाद है जहां पार्टी ने अपने आधार को बढ़ाया है तथा मजबूत किया है। राज्य में हुए पंचायत चुनाव में और त्रिपुरा आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद के चुनाव में भी, जो लोकसभा चुनाव के बाद हुए, पार्टी तथा वाम मोर्चा ने प्रगति दर्ज की है। बहरहाल, जैसाकि '19 वीं कांग्रेस द्वारा तय किए गए सांगठनिक कामों के परिपालन की मध्यावधि समीक्षा' में दर्ज किया गया था,

अन्य राज्यों में कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई है। अपने वर्तमान काम सूत्रबद्ध करते हुए हमें, इस स्थिति को हिसाब में लेना होगा।

2.56 पश्चिम बंगाल हमारी पार्टी का सबसे मजबूत आधार है। लोकसभा चुनाव के बाद से तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्ववाले गठजोड़ ने, हमारी पार्टी के खिलाफ हमला छेड़ रखा है। इसमें उसकी मदद कर रहे हैं माओवादी, जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं, सदस्यों व समर्थकों पर हमले कर रहे हैं। पंचायत चुनावों के बाद से, जिनमें ग्रामीण जनता के कुछ हिस्सों के बीच हमारे समर्थन में कुछ गिरावट आयी थी, तृणमूल के नेतृत्ववाले गठजोड़ ने अपना हमला ग्रामीण इलाकों पर केंद्रित किए रखा है। वे पार्टी व जनसंगठनों के कार्यालयों पर हमले कर रहे हैं या जबर्दस्ती उन पर कब्जे कर रहे हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों को जलाया या तोड़ा-फोड़ा जा रहा है। माओवादियों द्वारा चुन-चुनकर की गयी हत्याओं और तृणमूल कांग्रेस के नेतृत्ववाले गठजोड़ की हिंसा के चलते, पार्टी के 250 से ज्यादा सदस्य व समर्थक मारे गए हैं।

2.57 पार्टी को जनता को गोलबंद कर इन हमलों का प्रतिरोध करना होगा। इसके साथ ही साथ पार्टी ग्रामीण व शहरी मेहतनकशों की मांगें उठा रही है और आंदोलन चला रही है। सरकार के स्तर पर, प्राथमिकता देकर कुछ कामों को और विकास कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयत्न हो रहा है। सांगठनिक खामियों को दूर करने और जनता के साथ टूटी कड़ियां फिर से जोड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी तथा आंदोलन पर हो रहे हमले में साम्रज्यवादी एजेंसियां मदद कर रही हैं। इस चौतरफा हमले का मकसद देश में तमाम वामपंथी आंदोलन को कमजोर करना है। समूची पार्टी पूरी तरह से पश्चिम बंगाल इकाई के साथ खड़ी है और तृणमूल के नेतृत्ववाले कम्युनिस्टविरोधी गठजोड़ और माओवादियों द्वारा सी पी आइ (एम) के खिलाफ की जा रही हिंसा तथा हत्याओं के खिलाफ देश भर में जनतांत्रिक जनमत को गोलबंद करने का प्रयत्न करेगी।

2.58 नैगम मीडिया को, पार्टी तथा उसके नेतृत्व की आलोचना करने और पार्टी द्वारा अपनाए जा रहे रुख को तोड़-मोड़कर पेश करने के काम में जोता है। इसका आधार, नैगम मीडिया के अपने वर्गीय स्वार्थों में और नव-उदारवादी नीतियों के लिए उनके नंगे समर्थन में है। पिछले कुछ वर्षों में साम्राज्यवाद ने समाज के विभिन्न तबकों के बीच गहरी घुसपैठ की है। वामपंथविरोधी अभियान को उन हलकों से भी सहारा मिल रहा है, जो साम्राज्यवादी हितों के साथ गहराई से जुड़ गए हैं। सी पी आइ (एम) पर हमला, समग्रता में वामपंथी व प्रगतिशील विचारों पर ही हो रहे हमले का हिस्सा है। यह हमला नव-उदारवादी परियोजना का रास्ता आसान बनाने के लिए किया जा रहा है। इन हालात का तकाजा है कि पार्टी सिर्फ राजनीतिक मुद्दों से ही वास्ता न रखे बल्कि अपने विचारधारात्मक अभियान को भी तेज करे और सांस्कृतिक मोर्चे पर काम का विस्तार करे। इस हमले का मुकाबला करने के लिए, पार्टी के मीडिया तथा प्रचार के काम को भी मजबूत किया जाना चाहिए।

स्वतंत्र भूमिका: विकास की कुंजी

2.59 कुछ गिने-चुने इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पार्टी, अपने तीन मजबूत राज्यों से बाहर अपने आधार व प्रभाव को अब तक नहीं फैला पायी है। मौजूदा हालात में, जब पार्टी के सबसे मजबूत आधार, पश्चिम बंगाल पर हमला हो रहा है, यह और भी जरूरी हो जाता है कि अन्य राज्यों में पार्टी के प्रभाव व आधार का विस्तार किया जाए। पार्टी की स्वतंत्र भूमिका, पार्टी की प्रगति तथा उसके विकास की कुंजी है।

2.60 वर्गीय दृष्टिकोण को आधार बनाकर, पार्टी के राजनीतिक-विचारधारात्मक काम का विकास किया जाना चाहिए। सभी प्रमुख मुद्दों पर पार्टी का हस्तक्षेप होना चाहिए। पार्टी को, पूंजीवादी पार्टियों की विचारधारा और राजनीति की काट करनी चाहिए। पार्टी को, अपने राजनीतिक काम व अभियान को नये क्षेत्रों तथा नये तबकों के बीच ले जाना चाहिए।

2.61 बुनियादी वर्गों के बीच पार्टी के काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वर्गीय व जनसंगठनों के निर्माण में, किसानों व ग्रामीण गरीबों के बीच काम में पिछड़ पर काबू पाना होगा। पार्टी को संगठित क्षेत्र में, विनिर्माण व राणनीतिक उद्योगों में मजदूरों के बीच अपने प्रभाव का विस्तार करना होगा और इसके लिए प्रयास करने होंगे कि मजदूर वर्ग के असंगठित हिस्सों को आंदोलन में खींचा जाए और उनके बीच राजनीतिक काम किया जाए।

2.62 आम जनतांत्रिक मंच के हिस्से के तौर पर दलितों, अल्पसंख्यकों तथा महिलाओं के खास मुद्दों को उठाना होगा। पार्टी को, युवाओं व बेरोजगारों के बीच अपना राजनीतिक काम तेज करना होगा।

2.63 स्थानीय मुद्दों को उठाना और मांगों को हासिल करने के लिए अनवरत संघर्ष चलाना, पार्टी की एक मुख्य गतिविधि होनी चाहिए। यह संगठन को संघर्षोन्मुखी बनाने के लिए जरूरी है।

सामाजिक मुद्दों पर अभियान और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष

2.64 हमारी पार्टी दलितों, आदिवासियों, महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों के सामाजिक उत्पीड़न के मुद्दे उठाएगी। जातिवादी भेदभाव तथा सामाजिक उत्पीड़न के खात्मे के लिए संघर्ष, पूंजीवादी-भूस्वामी व्यवस्था के खिलाफ वर्गीय संघर्ष का हिस्सा है।

0 छुआछूत के खिलाफ और जातिवादी भेदभाव के सभी रूपों के खिलाफ, पार्टी अभियान चलाएगी और संघर्ष चलाएगी।

0 पार्टी को, मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा व रोजगार में आरक्षण पर, रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट के लागू किए जाने की मांग करनी चाहिए तथा उसके लिए अभियान चलाना चाहिए।

0 पार्टी को, लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पारित किए जाने के लिए अभियान चलाना चाहिए।

0 पार्टी को, आदिवासियों तथा पारंपरिक रूप से वनवासियों के लिए, वनाधिकार कानून के पालन के लिए काम करना चाहिए।

2.65 पूंजीवादी पार्टियों द्वारा जो जाति-आधारित राजनीति तथा जाति की दुहाई का सहारा लिया जाता है, उससे जातिवादी उत्पीड़न व भेदभाव का अंत नहीं होता है। उल्टे इस तरह की पहचान की राजनीति, जाति-विभाजनों को बनाए रखने का ही काम करती है। सी पी आइ (एम), सामाजिक उत्पीड़न के सभी मुद्दों को उठाएगी और इसके लिए भी प्रयास करेगी कि सभी जातियों में जन्मे उत्पीड़ितों को, अपने साझा वर्गीय शोषण के खिलाफ संघर्ष के लिए गोलबंद किया जाए।

आंदोलनों को व्यापकतर बनाओ और तेज करो

2.66 हाल के दौर में पार्टी और वामपंथ ने महंगाईविरोधी आंदोलन उठाया है। 8 अप्रैल के सत्याग्रह (पिकेटिंग) तथा गिरफ्तारियों के कार्यक्रम में बीस लाख लोगों ने शिरकत की थी। इसके बाद, 27 अप्रैल को 13 पार्टियों के आह्वान पर हड़ताल हुई, जो सफल रही। 5 जुलाई की हड़ताल, जिसका आह्वान वामपंथ व धर्मनिरपेक्ष विपक्षी पार्टियों ने किया था, पिछले दो दशकों की सबसे बड़ी विरोध कार्रवाई साबित हुई। एनडीए ने भी उसी रोज बंद का आह्वान किया था। नौ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से, 7 सितंबर 2010 को हड़ताल का आह्वान किया है। कोयला मजदूरों, इस्पात मजदूरों, बी एस एन एल कर्मचारियों तथा आंगनवाड़ीकर्मियों की, उद्योग-क्षेत्रवार हड़तालें हुई हैं। हालांकि ये संघर्ष उल्लेखनीय हैं, ये नव-उदारवादी नीतियों के हमले का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं हैं। हमें नरेगा के समुचित परिपालन, खाद्य सुरक्षा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सार्वजनीकरण के लिए आंदोलन चलाने चाहिए। हमें जनांदोलनों के विकास तथा

संघर्षों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और संयुक्त संघर्ष चलाने चाहिए ताकि हमारे दायरे के बाहर के मेहनतकशों को भी संघर्षों में खींचा जा सके।

वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारों की रक्षा करो

2.67 पश्चिम बंगाल, केरल तथा त्रिपुरा की वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारों का भूमि सुधार लागू करने, पंचायतों के पक्ष में शक्तियों का विकेंद्रीकरण करने, जनता के अधिकारों व आजीविका की हिफाजत करने के लिए जनहितकारी कदम उठाने और एक स्थिर, धर्मनिरपेक्ष वातावरण बनाए रखने का उल्लेखनीय रिकार्ड है।

2.68 पश्चिम बंगाल की वाम मोर्चा सरकार ने भूमि सुधारों को लागू करने के लिए सबसे ज्यादा काम किया है। इस राज्य में हदबंदी से फालतू जमीन का वितरण किए जाने के अलावा, जिसके तहत देश भर में बांटी गयी हदबंदी से फालतू कुल जमीन का 22 फीसद हिस्सा वितरित किया गया था, 2007 से 2010 के बीच ही भूमिहीन परिवारों के बीच 16,700 एकड़ भूमि और बांटी गयी है। किसानों के लिए सरकारी सहायता की मदद से इस राज्य में 4 फीसद से ऊपर की कृषि वृद्धि दर बनाए रखना संभव हुआ है, जबकि पूरे देश के पैमाने पर कृषि वृद्धि दर में भारी गिरावट हुई है। गरीबी की रेखा के नीचे के 2 करोड़ 46 लाख परिवारों को, 2 रुपए प्रति किलोग्राम पर चावल दिया जा रहा है। जहां तक मजदूर वर्ग का सवाल है, पेंशन व प्रोवीडेंट फंड योजनाओं का असंगठित क्षेत्र के मजदूरों तक विस्तार किया गया है और इसमें 17 लाख मजदूरों को भर्ती किया गया है। बंद फैक्टरियों के मजदूरों को 1500 रु0 महीना पेंशन दी जा रही है। राज्य सरकार ने, 100 रु0 की दिहाड़ी पर शहरी रोजगार गारंटी की योजना का भी एलान किया है।

2.69 केरल की एलडीएफ सरकार के प्रशासन में, ऋण राहत विधेयक तथा कदमों के जरिए किसानों की आत्महत्याओं पर अंकुश लगा है। राज्य के सार्वजनिक उद्यमों में नयी जान डाली गयी है। जहां 2006 में राज्य की कुल 45 सार्वजनिक क्षेत्र कंपनियों में से 12 ही लाभ में चल रही थीं, 2009-10 में पूरी 32 कंपनियां मुनाफे में आ चुकी थीं और उन्होंने 240 करोड़ रु0 का लाभ कमाया था। इस राज्य में 35 लाख परिवारों को, जिनमें खेती व परंपरागत उद्योगों में लगे सभी असंगठित मजदूर तथा मछुआरे शामिल हैं, 2 रु0 प्रति किलोग्राम की दर से चावल बांटा जा रहा है। सरकार ने ई एम एस आवास योजना के अंतर्गत, राज्य के सभी गृहहीन परिवारों को घर मुहैया कराने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत 5 लाख घर बनाने का लक्ष्य है। राज्य में एक शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू की गयी है। इसके साथ ही साथ, परंपरागत उद्योगों के मजदूरों के लिए एक आय सहायता योजना चलायी जा रही है। सभी गरीब परिवारों तक स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा का विस्तार किया गया है और पेंशनों में बढ़ोतरी की गयी है।

2.70 त्रिपुरा की वाम मोर्चा सरकार ने, राजनीतिक गोलबंदी तथा विकास संबंधी कदमों के साथ ही साथ, जो कड़े प्रशासनिक कदम उठाए हैं, उग्रवादी गुटों द्वारा हिंसा के उपयोग पर कड़ा अंकुश लगा है और राज्य के ऐसी हिंसा से ग्रसित इलाकों में शांति बहाल हुई है। नरेगा के परिपालन में 2009-10 में यहां प्रति व्यक्ति सालाना 82 दिन का काम मुहैया कराया गया है, जो देश भर में सबसे ज्यादा है। त्रिपुरा ऐसा पहला राज्य था जिसने ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का शहरी इलाकों तक विस्तार किया था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पंद्रह केंद्रों में, गरीबी की रेखा के नीचे के परिवारों को, 75 दिन का रोजगार मुहैया कराया जा रहा है। पेंशन का विस्तार कर के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी उसके दायरे में लाया गया है। प्राइमरी स्तर पर स्कूल जाना छोड़ जाने वालों का अनुपात अब घटकर 4.5 फीसद रह गया है, जबकि 2001 में यही अनुपात 50.5 फीसद था। कालेज स्तर तक लड़के-लड़कियों से कोई ट्यूशन फीस नहीं ली जा रही है। आदिवासी स्वायत्त जिला परिषद के क्षेत्र में शिक्षा, शिशु देखभाल तथा स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं के प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। त्रिपुरा वन

अधिकारों को लागू करने के मामले में आगे-आगे रहा है। यहां 1 लाख 16 हजार परिवारों को 1 लाख 70 हजार हैक्टेयर जमीन के पट्टे बांटे गए हैं।

2.71 तमाम सीमाओं के बावजूद वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारें, विभिन्न जनहितकारी कदमों का आगे बढ़ाने के प्रयास कर रही हैं। चूंकि ये सरकारें ऐसी ताकतों ने बनायी हैं जो नव-उदारवादी नीतियों के विकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं, प्रतिक्रियावादी ताकतों तथा निहित स्वार्थों की ओर से उन पर हमले हो रहे हैं। वामपंथी नेतृत्ववाली सरकारों और वे जिन नीतियों पर चल रही हैं उनकी हिफाजत करना, देश की वामपंथी व जनतांत्रिक शक्तियों का एक महत्वपूर्ण काम है।

वामपंथी एकता

2.72 हाल के दौर में वामपंथी पार्टियों की पहलों व संयुक्त आह्वानों में बढ़ोतरी हुई है। इसकी शुरूआत 12 मार्च की रैली से हुई थी और यह प्रक्रिया अखिल भारतीय हड़तालों में अपने उत्कर्ष पर पहुंची है।

2.73 स्वतंत्र भूमिका के हिस्से के तौर पर हमें वामपंथी तथा जनवादी विकल्प को सामने लाना चाहिए और वामपंथ की और ज्यादा संयुक्त कार्रवाइयां छेड़ने के जरिए, वामपंथी एकता के मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए। पार्टी को वामपंथी विचार वाले उन संस्तरों के साथ दोबारा कड़ियां जोड़ने के लिए काम करना होगा, जो हमसे दूर हो गए हैं।

संगठन को मजबूत करो

2.74 मौजूदा परिस्थितियों में अपने कामों को पूरा करने के लिए यह जरूरी है कि:

(अ) जनवादी केंद्रवाद के सिद्धांतों के आधार पर पार्टी संगठन को चुस्त-दुरुस्त किया जाए; पार्टी को और संघर्षों के जरिए हासिल हुए प्रभाव को राजनीतिक व सांगठनिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए कदम उठाए जाएं।

(ब) ब्रांचों व अन्य कमेटियों के समुचित काम-काज के जरिए और सुव्यवस्थित पार्टी शिक्षण के जरिए, पार्टी के सदस्यों के राजनीतिक-विचारधारात्मक स्तर को ऊपर उठाने के लिए कदम उठाए जाएं। पार्टी में सभी स्तरों पर दुरुस्तीकरण अभियान चलाया जाए ताकि खामियों व गलत तौर-तरीकों को दूर कर, पार्टी की एकता को मजबूत किया जा सके।

(स) जनसंगठनों के प्रति पार्टी सही रुख अपनाए और उनके स्वतंत्र व व्यापक आधारवाले स्वरूप का विकास करने में मदद करे।

मौजूदा काम

2. 75 क्या करने की जरूरत है?

(अ) कुंजीभूत काम है तमाम नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ लड़ना, जो सभी क्षेत्रों में जनता की जिंदगियों को प्रभावित कर रही हैं। ये नीतियां, जिनकी आग साम्राज्यवादी विश्वीकरण द्वारा भड़कायी जा रही है, अमीरों को और अमीर बना रही हैं तथा नैगम कंपनियों व बड़ी पूंजी के हाथों में संसाधनों का हस्तांतरण कर रही हैं। ये नीतियां मेहतनकश जनता के हितों के लिए नुकसानदेह हैं। कांग्रेस के नेतृत्ववाली यूपीए सरकार, 2004 में सत्ता में आने के गुजरे छ: वर्षों में इन्हीं नीतियों पर चलती रही है।

(आ) नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष का अर्थ है, दो स्तरों पर संघर्ष। पहला, केंद्र तथा संबंधित राज्य सरकारों की नीतियों के स्तर पर संघर्ष। दूसरा, जनता के जीवन स्तर, भूमि, रोजगार सुरक्षा, समुचित मजदूरी, स्वास्थ्य रक्षा सुविधाओं तक पहुंच, शिक्षा तथा बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाना, जिनके मामले में जनता के हितों पर नव-उदारवादी नीतियों का प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पार्टी तथा

जनसंगठनों को स्थानीय मुद्दों पर सतत संघर्ष चलाने होंगे और जनता के मुद्दों पर राज्यव्यापी आंदोलन भी छेड़ने होंगे। अखिल भारतीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर, नव-उदारवादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने होंगे।

(इ) सांप्रदायिक राजनीति, जो सांप्रदायिक एजेंडा को आगे बढ़ाने की कोशिशों में लगी हुई है, अब भी खतरा पेश कर रही है। आर एस एस और उसका राजनीतिक बाजू, भाजपा, बहुसंख्यक सांप्रायिकता तथा हिंदुत्ववादी विचारधारा के मुख्य औजार हैं। हालांकि भाजपा को चुनावी धक्के लगे हैं, उसकी सांप्रदायिक गतिविधियों में कोई कमी नहीं आयी है। आने वाले दिनों में सांप्रदायिकता के खिलाफ तथा हिंदुत्व-आधारित गतिविधियों के खिलाफ संघर्ष चलाना होगा। इसके साथ ही साथ पार्टी को, अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता व अतिवाद का मुकाबला करने के लिए भी सतर्क रहना चाहिए।

(ई) यूपीए सरकार सभी स्तरों पर अमरीका के साथ रणनीतिक गठजोड़ को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और इसमें सैन्य गठजोड़ भी शामिल है। यह रणनीतिक गठजोड़ हमारे देश की घरेलू नीतियों पर असर डाल रहा है और एक स्वतंत्र विदेश नीति के रास्ते की मुख्य बाधा है। पार्टी को, भारत-अमरीका रणनीतिक गठजोड़ और उसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों के खिलाफ अपना विरोध तेज करना होगा। पार्टी को, अमरीका के साथ इस गठजोड़ के खिलाफ तमाम देशभक्त, जनतांत्रिक हलकों को जत्थेबंद करना होगा और एक स्वतंत्र विदेश नीति के पालन के पक्ष में तथा दुनिया भर में साम्राज्यवादी दखलंदाजियों के खिलाफ, जनता को गोलबंद करना होगा।

(उ) पार्टी को, यूपीए सरकार की नव-उदारवादी नीतियों की मुख्य संचालक कांग्रेस का विरोध करना चाहिए, जो बड़े पूंजीपतियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है और अमरीकापरस्त विदेश नीति की पक्षधर है।

(ऊ) भाजपा सांप्रदायिक राजनीति का ही व्यवहार नहीं करती है, यह एक दक्षिणपंथी पार्टी है जो नव-उदारवादी नीतियों का प्रतिनिधित्व करती है। पार्टी, राजनीतिक रूप से भाजपा का मुकाबला करेगी और उसे अलग-थलग करने के लिए धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करने की कार्यनीति अपनाएगी।

(ए) सी पी आइ (एम), संसद में तथा संसद के बाहर भी, उन गैर-कांग्रेसी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों का सहयोग हासिल करने का प्रयास करेगी जो जनता के मुद्दों को उठाने के लिए, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने के लिए और राष्ट्रीय संप्रभुता के क्षय का विरोध करने के लिए, साथ आने के लिए तैयार होंगे। जहां भी जरूरी हो, ऐसी पार्टियों के साथ चुनावी समझदारी भी बनायी जा सकती है।

(ऐ) पार्टी अपनी स्वतंत्र भूमिका व गतिविधियों पर जोर देगी। पार्टी, वामपंथ की वैकल्पिक नीतियां जनता के सामने रखेगी। पार्टी, वामपंथी एकता को मजबूत करने के लिए तथा वामपंथ की शक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए काम करेगी और इसके साथ ही साथ, माओवादियों की विघटनकारी नीतियों के खिलाफ दृढ़निश्चय संघर्ष चलाएगी।

(ओ) समूची पार्टी, पश्चिम बंगाल में सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ की रक्षा करने के लिए, हिंसक हमलों का मुकाबला करने में मदद करने के लिए तथा प्रतिकूल हालात पर काबू पाने के लिए, जनता तथा जनतांत्रिक ताकतों को गोलबंद करने के लिए काम करेगी।

(औ) सी पी आइ (एम), मांगों के वामपंथी व जनवादी मंच के आधार पर, जनविरोधी नीतियों का मुकाबला करने के लिए और मेहनतकशों की आजीविका व अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष में मजदूर वर्ग, किसानों, खेत मजदूरों, दस्तकारों तथा मेहनतकशों के अन्य तबकों को गोलबंद करेगी। कांग्रेस तथा अन्य पूंजीवादी पार्टियों के प्रभाव में जो अवाम हैं उन्हें, उनके मुद्दों व समस्याओं पर एकजुट संघर्षों में खींचने के जरिए, अपने पक्ष में करने पर पार्टी को ध्यान देना चाहिए।

(अं) पार्टी, आम जनतांत्रिक मंच के हिस्से के तौर पर दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं व अन्य उत्पीड़ित तबकों के अधिकारों का झंडा बुलंद किए रहेगी।

2.76 भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की केंद्रीय कमेटी की विस्तारित बैठक, समूची पार्टी का आह्वान करती है कि एकजुट होकर इन कामों को हाथ में ले और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करे। जनता के हितों तथा जनतांत्रिक अधिकारों का झंडा उठाने में; भूमि, भोजन, रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के लिए उनके संघर्षों का नेतृत्व करने में, हमें सबसे आगे की कतार में रहना चाहिए। हमें धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी होगी और सांप्रदायिकता की ताकतों को अलग-थलग करना होगा। हमें साम्राज्यवादी धावों से राष्ट्रीय संप्रभुता की हिफाजत करनी होगी। जो सी पी आइ (एम) तथा वामपंथ को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी कोशिशों को विफल किया जाएगा। हम, वर्गीय शोषण के खिलाफ और सभी उत्पीड़ित तबकों के लिए, सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष के रास्ते पर बढ़ेंगे। 0